

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:- श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्या:- 51/2021 (GCMS No. 2021/55) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. रामप्रसाद पुत्र लादू जाति जाट उम्र 50 साल पेशा काश्त निवासी महापुरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला जिला सवाई माधोपुर।

.....अपीलान्त

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा।



.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार चौथ का बरवाडा दिनांक 10.10.2019 प्र.सं. 308/19 उनवान सरकार बनाम रामप्रसाद एवं आदेश अति. जिला कलक्टर सवाई माधोपुर दिनांक 10.05.2021 मुकदमा नं. 48/2020 उनवानी रामप्रसाद बनाम सरकार।

उपस्थिति:-

1. श्री जगन्नाथ जाट, वकील अपीलान्त
2. राजकीय अभिभाषक, वकील रेस्पोडैन्ट

नि र्ण य

दिनांक : 07.07.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत आदेश जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 10.05.2021 एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा के आदेश दिनांक 10.10.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौथ का बरवाडा ने दिनांक 10.10.2019 को अपीलान्त को आराजी खसरा नम्बर 1285 रकवा 0.10 ऐयर वाके ग्राम महापुरा में बाडा बनाकर, चरी बोकर चारागाह भूमि पर अतिक्रमी मानकर तीन माह की सिविल कारावास एवं लगान की 50 गुना पेनल्टी के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिसकी अपील अपीलान्त द्वारा अति. जिला कलक्टर सवाई माधोपुर

को पेश की गई, जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। जिनके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। वहस उभयपक्ष सुनी गई।
3. दौराने वहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अराजी खसरा नम्बर 1285 रकवा 0.10 ऐयर भूमि वाके ग्राम महापुरा पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सजा से दण्डित करने में भूल की है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। तहसीलदार ने चारागाह भूमि को दिनांक 05.12.2010 से लेकर 12.12.2019 के बीच अतिक्रमण मुक्त कर दिया है तथा बेदखल किया जा चुका है। अपीलान्ट की सही प्रकार से तामील नहीं हुई है। सबूत सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का निर्णय है कि जब तक अपीलान्ट को मौके पर जाकर भौतिक रूप से विवादित भूमि से बेदखल नहीं कर दिया जाता, तब तक अपीलान्ट को सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता। प्रकरण में कब्जे, मौके से बेदखली तथा स्वतंत्र गवाहान के बयान नहीं लिये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई एवं सबूत पेश करने को कोई अवसर नहीं दिया तथा प्रिन्टेड प्रोफार्मा पर निर्णय दिया है। तहसीलदार ने मौके पर जाकर कब्जे की कोई जाँच नहीं की। पटवारी हल्का के बयान भी प्रिन्टेड प्रोफार्मा में लिये गये। जिरह तथा सबूत दस्तावेजात पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलान्ट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। न ही पूर्व में पारित बेदखली के बावत् उपस्थित गवाहान के बयान लिये गये। अपीलान्ट को गलत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है। वर्ष 2019 के बाद से मौके पर कब्जा नहीं है। मौका रिपोर्ट प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के साथ पेश की जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौथ का बरवाडा एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर का निर्णय अपास्त किया जाकर अपीलान्ट को दोषमुक्त किया जावे। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के समर्थन में माननीय न्यायालय की न्यायिक नजीर आरआरडी 1979 पेज 559 पेश की है।
4. राजकीय अभिभाषक द्वारा वहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत अपीलाधीन आदेश

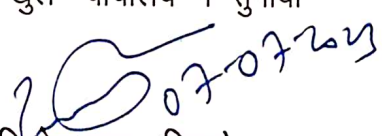


2 अतिरिक्त संभागीय आबुस्त
भरतपुर

पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय बहाल रखा जावे।



5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालय की नजीर का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश प्रथम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.02.2021 को पारित किया गया, जिसके विरुद्ध दिनांक 08.07.2021 को न्यायालय हाजा में द्वितीय अपील पेश की गई। अपीलान्त द्वारा अपने तर्कों में मुख्य कथन किया कि पश्चातवर्ती अतिक्रमण का कोई साक्ष्य नहीं है। पूर्व में पारित बेदखली के समय उपस्थित गवाहान के बयान नहीं लिये गये हैं। वर्ष 2019 के बाद अपीलान्त का कब्जा नहीं है। तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 12.12.2019 द्वारा दिनांक 05.12.2019 से 12.12.2019 तक ग्राम महापुरा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाकर कब्जेराज लिया जाकर डौल लगवाई जा चुकी है। उक्त तथ्यों के आलोक में न्यायालय के मत में चूंकि वर्तमान में आराजी पर अपीलान्त का कब्जा शेष नहीं रहा। तदनुसार सहानूहतिपूर्वक विचार करते हुये अपील आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।
6. अतः अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलान्त को निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौथ का बरवाडा के यहाँ विवादित आराजी पर भविष्य में अतिक्रमण न किये जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.10.2019 में उल्लेखित 3 माह के सिविल कारावास के दण्डादेश को निरस्त किया जाता है। शेष आदेश बदस्तूर रहेगा। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ़्तर हो।
7. निर्णय आज दिनांक 07.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अश्लिश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर